10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन

- स्काच समूह ने आर्थिक नीतियों के अध्ययन के आधार पर अपनी ताजा रिपोर्ट में किया दावा
- सरकार की नीतियों व स्कीमों से 19.79 करोड़ रोजगार का सृजन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले दस साल (2014-24) के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। इनमें 19.79 करोड़ रोजगार का सृजन सरकार की विभिन्न स्कीम व नीतियों की वजह से हुआ तो 31.61 करोड़ रोजगार बैंकों की तरफ से कारोबार के लिए दिए गए कर्ज की वजह से संभव हो सका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुद्रा योजना की मदद से हर साल औसतन 3.16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यह दावा स्काच ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह समूह आर्थिक-सामाजिक मुद्दों पर काम करता है।

समूह ने मुद्रा योजना से जुड़े लोगों पर सर्वे करने के साथ सरकार की आर्थिक नीतियों पर अध्ययन कर यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण स्व रोजगार एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि से लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में मोदीनामिक्स की बदौलत तेजी से वित्तीय समावेश हुआ और लोगों को बैंक से कर्ज मिलना आसान हो गया। मुद्रा योजना के तहत छोटे-छोटे शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में छोटी-छोटी राशि के कर्ज दिए गए। इस प्रकार के कर्ज से स्वरोजगार व आंशिक रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सरकार से पहले यह माना जाता था कि छोटी-छोटी राशि से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। मौजूदा सरकार ने इस सोच को गलत साबित किया। सर्वे के दौरान पाया गया कि सिर्फ 85,000 रुपये के कर्ज से टिकाऊ रोजगार का सृजन हो सकता है। सरकार के कार्यक्रम से कर्ज मिलने के मामले में बड़े और छोटे कारोबारियों के बीच का अंतर कम होता गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी बार उन कारोबारियों को ही छोटे लोन दिए गए जिन्होंने पहले लोन का भुगतान कर दिया। ऐसा पाया गया कि दूसरी बार लोन लेने वालों ने अपने कारोबार का विस्तार किया।